



इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने से राहत में चीनी मिलें

[पीटीआई | मुंबई]

सरकार के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ने और चीनी की बिक्री की लिमिट तय करने के बाद से मिलों का मुनाफा बढ़ रहा है। इससे किसानों को समय पर गन्ने का भुगतान मिलने की उम्मीद है। सरकार ने इस महीने के शुरुआत में ही सस्ती चीनी का आयात रोकने के लिए रॉ और वाइट शुगर पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाकर 100 परसेंट कर दिया था। केंद्र ने फरवरी और मार्च में गिरती कीमतों को रोकने के लिए स्टॉक होल्डिंग की लिमिट तय कर दी थी।

रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने एक रिपोर्ट में कहा, 'सरकार के कदमों से चीनी के दाम में गिरावट रुकेगी। इससे मिलों का मुनाफा बढ़ेगा। उनकी क्रेडिट प्रोफाइल भी स्टेबल रही है।' रिपोर्ट के मुताबिक, इससे किसानों को भी फायदा होगा और उन्हें गन्ने का समय पर भुगतान मिल जाएगा। सरलास प्रॉडक्शन के अनुमान के चलते अक्टूबर 2017 से जनवरी 2018 के बीच चीनी के दाम में 18 परसेंट गिरावट आई थी। इसके साथ ही चालू सीजन (अक्टूबर-सितंबर) में गन्ने के दाम में 11 परसेंट की बढ़ोतारी से भी मिलों के मुनाफे पर असर पड़ा। क्रिसिल के सीनियर डायरेक्टर सुबोध राय के अनुसार, सरलास प्रॉडक्शन के चलते ग्लोबल शुगर प्राइस भी पिछले सीजन के औसत कीमत से नीचे आ चुका है। उन्होंने कहा, 'इसलिए हमें लगता है कि घरेलू संतुलन को बनाए रखने और चीनी मिलों के हितों रक्षा के लिए कस्टम ड्यूटी को 100 परसेंट करने का निर्णय सही समय पर किया गया हस्तक्षेप है। राय का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत में गिरावट आने पर इससे इंटीग्रेटेड मिलों को प्रति किलो 6-7 रुपये तक का स्पॉर्ट मिलेगा।'

क्रिसिल का अनुमान है कि अच्छे मौनसून और गन्ने के ज्यादा रक्खे से चालू सीजन में चीनी का उत्पादन 2.6 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। यह पिछले सीजन से 60 लाख टन ज्यादा है। हालांकि, मांग 2.5 करोड़ टन पर स्थिर रहने की उम्मीद है। रेटिंग एजेंसी के मुताबिक, दो महीने तक मिलों के लिए लिमिट तय किए जाने से पिछले महीने के क्लोजिंग स्टॉक को कम से कम 83-86 परसेंट तक रखने की जरूरत है। इसके साथ फरवरी और मार्च के कोटे के बिक्री एक ही महीने में नहीं होनी चाहिए। इससे बाजार में चीनी की सप्लाई काबू में रहेगी। क्रिसिल के डायरेक्टर मनीष गुप्ता ने कहा, 'हम अगले सीजन में गन्ने की कीमतों में होने वाले बदलाव को जानने के लिए रक्खे और रेगुलेटरी उपायों पर करीबी नजर बनाए हुए हैं।'

The Economic Times
21-02-18.

✓ ✓